कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत उन किसानों को सस्ती दरों पर बिजली, पानी और कृषि-उपकरण उपलब्ध कराने और सहकारिता के आधार पर ट्रैक्टर देने तथा कम ब्याज पर ऋण देने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं ; और

(ग) क्या योजना को लागू करने के लिए प्रशासन तंत्र ठीक कर दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनायें शुरू की गई है जिन में से एक छोटे, लेकिन सम्भाव्य सक्षमता वाले किसानों के लिये है जिनके पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच भूमि है और दूसरी सीमान्त किसानों व कृषि मजदूरों के लिये है, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है ।

(ख) और (ग). योजना में छोटे कृषकों की समस्याओं का पता लगाने समुचित कार्यक्रम तैयार करने, आदानों की समय पर निश्चित आपूर्ति करने तथा कृषकों को सेवाई एवं ऋण प्रदाब करने के लिये परियोजना क्षेत्रों में समन्वयकारी एजेन्सियों की स्थापना की व्यवस्था है । ये एजेन्सियां जहां तक सम्भब हो यह कार्य वर्तमान संस्थाओं अथवा प्राधिकारियों के माध्यम से करेंगी । ये एजेन्सियां सस्था पंजीकरण नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। प्रायः जिला कलक्टर इन एजेन्सियों के अध्यक्ष होते हैं और विकास विभाग तथा सहकारी संस्थाओं के जिला अधिकारियों सहित दो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं । ये एजेन्सियाँ सहकारी समितियों को जोखिम-निधि अंशदान प्रदान करती हैं और कुछ मदों के लिये राज सहायता भी प्रदान करती है ताकि छोटे किसान विकास कार्यक्रम शुरू कर सकें और ऋण के रूप में सहायता प्राप्त कर सकें । भूमि विकास द्वारा कृषि में सुधार, लघु सिंचाई कार्य, उन्नत कृषि उपकरणों तथा अन्य आदानों का प्रयोग लघु कृषक विकास एजेन्सी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।

Girdih collieries under National Coal Development Corporation

*1016. SHRI CHAPAL BHATTACHARYYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Giridih collieries producing the finest metallurgical coal in India and manufacturing premium coke were operated by National Coal Development Corporation under Presidential Directive between 1959 to 1968 ;

(b) whether Government have decided to reimburse the losses suffered by N.C.D.C. for carrying out the Presidential Directive ;

(c) if not, the time by which Government propose to decide the same ;

(d) whether enquiries from foreign countries for Giridih Coal have quoted a price up to Rs. 150/—per tonne ; and

(e) if so, the outcome of the negotiations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) The Giridih Collieries are being oprated by National Coal Development Corporation under Presidential Directive issued in September, 1960.

(b) and (c). The question of reimbursement of losses is under consideration of the Government aud a decision is expected to be taken shortly.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Report of Manganese ore (India) Ltd.

*1017. SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the report of Manganese Ore (India) Ltd. which was to be placed before the Lok Sabha (1971) has been stolen ; and